टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना: वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

- यूपीएससी-प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता: टीआरएफ, लश्कर-ए-तैयबा, यूएपीए, एनआईए अधिनियम, यूएनएससी 1267 समिति, एफएटीएफ और आतंकवाद का वित्तपोषण
- **मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:**
- ● आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ
- ● आतंकवाद से निपटने में प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी की भूमिका
- ● सीमा सुरक्षा और घुसपैठ
- **निबंध अभ्यास:**
- ● "आतंकवाद की कोई सीमा नहीं: वैश्विक सहयोग, भारत की ज़िम्मेदारी"

समाचार में क्यों?

- 17 जुलाई, 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) के रूप में घोषित किया।
- यह निर्णय जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF द्वारा लेने के बाद आया है।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने इस निर्णय को "समयबद्ध और महत्वपूर्ण कदम" बताया, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि

- TRF को व्यापक रूप से पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की छद्म इकाई माना जाता है। LeT 2008 के मुंबई हमलों जैसे कई बड़े आतंकी हमलों के लिए ज़िम्मेदार रहा है।
- हालाँकि LeT को पहले से ही आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा चुका है, यद्यपि TRF अब तक वैश्विक निगरानी से बचता रहा था। अमेरिका द्वारा उठाया गया यह कदम इस कमी को पूरा करता है तथा सीमापार आतंकवाद में पाकिस्तान द्वारा छद्म समूहों के उपयोग को उजागर करने के भारत के प्रयासों को मजबूत करता है।यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति पर TRF को वैश्विक खतरे के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए राजनयिक दबाव बना रहा है।

आतंकवाद क्या है?

- आतंकवाद, राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से नागरिकों के विरुद्ध, हिंसा और धमकी का गैरकानूनी प्रयोग है।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करता है और सामाजिक सद्भाव को कमज़ोर करता है।

आतंकवाद के प्रकार एवं उदाहरण

- 1. धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism)
- परिभाषा: ऐसा आतंकवाद जो धार्मिक विचारधाराओं से प्रेरित होता है, जहाँ हिंसा को ईश्वरीय आदेश बताकर उचित ठहराया जाता है।

उदाहरण:

- आईएसआईएस (ISIS): वैश्विक जिहादी हमलों का संचालन; 2015 पेरिस हमले शामिल।
- लश्कर-ए-तैयबा (LeT): 2008 मुंबई हमलों का दोषी; दक्षिण एशिया में इस्लामी राज्य की स्थापना का लक्ष्य।

2.. जातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद *(Ethno-nationalist Terrorism)*

- परिभाषा: ऐसा आतंकवाद जो किसी विशिष्ट जातीय या क्षेत्रीय पहचान के लिए स्वतंत्रता या स्वायत्तता की माँग करता है।

उदाहरण:

- उल्फा (ULFA): स्वतंत्र असम की माँग करने वाला संगठन; बम धमाकों और फिरौती में लिप्त।
- एलटीटीई (LTTE): श्रीलंका में तमिल मातृभूमि के लिए संघर्ष; 1991 में राजीव गांधी की हत्या की।

3. वामपंथी उग्रवाद *(Left-Wing Extremism)*

- परिभाषा: मार्क्सवादी या माओवादी विचारधारा से प्रेरित सशस्त्र संघर्ष, जो लोकतांत्रिक या पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है।

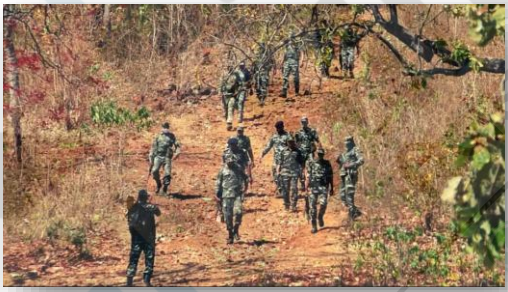

उदाहरण:

- सीपीआई (माओवादी): छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में सक्रिय; बारूदी सुरंगों और घात लगाकर हमलों के लिए कुख्यात।
- पीपुल्स वार ग्रुप (PWG): माओवादी संगठन का पूर्ववर्ती रूप; राज्य बलों के खिलाफ छापामार युद्ध में लिप्त।

4. राज्य प्रायोजित आतंकवाद *(State-Sponsored Terrorism)*

- परिभाषा: जब कोई देश छिपे रूप में आतंकवादी समूहों को समर्थन देता है ताकि शत्रु देशों को अस्थिर किया जा सके या अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके।

उदाहरण:

- पाकिस्तान द्वारा टीआरएफ को समर्थन: लश्कर-ए-तैयबा का छद्म संगठन, जिसका उपयोग जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने हेतु किया गया।
- ईरान द्वारा हिज़बुल्ला को समर्थन: ईरानी प्रभाव को पश्चिम एशिया में फैलाने के लिए उग्रवादी गतिविधियाँ।

5. साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)

- परिभाषा: डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण ढाँचों पर हमला, गोपनीय जानकारी की चोरी, या डर फैलाने वाली गतिविधियाँ।

उदाहरण:

- 2020 कूडनकुलम परमाणु संयंत्र पर मालवेयर हमला: उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा भारतीय परमाणु ढाँचे में सेंध की आशंका।
- एस्टोनिया 2007 साइबर हमला: रूस समर्थक हैकरों पर दोष; देश में डिजिटल संचार ठप हुआ।

6. सीमा पार आतंकवाद (Cross-Border Terrorism)

- परिभाषा: जब आतंकवादी हमले दुश्मन देशों या गैर-राजकीय तत्वों द्वारा किसी देश की सीमा पार से संचालित या समर्थित होते हैं।

उदाहरण:

- 2001 भारतीय संसद पर हमला: जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पाकिस्तान स्थित आतंकियों द्वारा किया गया।
- 2016 उरी हमला: पाकिस्तान स्थित आतंकियों ने नियंत्रण रेखा पार कर जम्मू-कश्मीर में हमला किया।

आतंकवाद के प्रमुख कारण

1. धार्मिक कट्टरपंथ

- व्याख्या: धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों की अति-चरमपंथी व्याख्या जो कुछ व्यक्तियों या समूहों को यह विश्वास दिलाती है कि हिंसा ईश्वरीय रूप से न्यायोचित है।
- उदाहरण: आईएसआईएस (ISIS) का प्रचार और ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण ने वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रभावित किया, जिसमें केरल के युवा भी शामिल रहे जिन्होंने ISIS को जॉइन किया।

2. राजनीतिक उपेक्षा और अलगाववाद

- व्याख्या: जब किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा जाता है, अधिकारों से वंचित किया जाता है, या क्षेत्रीय स्वायत्तता नहीं दी जाती, तो वे अलगाववादी आंदोलनों की ओर बढ़ते हैं, जो बाद में उग्रवाद या आतंकवाद में परिवर्तित हो सकते हैं।
- उदाहरण: असम में ULFA द्वारा स्वतंत्रता की माँग, और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन।

3. सीमा पार हस्तक्षेप

- व्याख्या: कुछ विदेशी शक्तियाँ आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण, हथियार, और सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराकर दूसरे देशों को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं।
- उदाहरण: पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) द्वारा भारत में कई बड़े हमले किए गए हैं।

4. खराब शासन और कमज़ोर कानून प्रवर्तन

- व्याख्या: अपर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार और अप्रभावी पुलिस व्यवस्था, चरमपंथी नेटवर्क को, खासकर दूरदराज के इलाकों में, बेखौफ होकर पनपने और काम करने का मौका देती है।
- उदाहरण: रेड कॉरिडोर (Red Corridor) में माओवादी प्रभाव का विस्तार राज्य की कमजोर उपस्थिति और शासन के अभाव का परिणाम है।

5. असुरक्षित क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी

- व्याख्या: जब युवाओं को रोज़गार, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, तो वे कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और आतंकी संगठनों की भर्ती का आसान निशाना बनते हैं।

6. चरमपंथी विचारधाराओं के प्रचार में सोशल मीडिया का उपयोग

- व्याख्या: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर घृणा फैलाने वाली भाषा, उग्रवादी सामग्री, और आतंकी संगठनों की भर्ती से जुड़ा प्रचार तेज़ी से फैलता है और अक्सर निगरानी से बच निकलता है।
- उदाहरण: बुरहान वानी की ऑनलाइन लोकप्रियता और कश्मीर में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से डिजिटल कट्टरपंथीकरण।

भारत में प्रमुख आतंकवादी हमले (हालिया एवं पूर्ववर्ती)

वर्ष	हमला	स्थान	आतंकी संगठन
2001	संसद पर हमला	दिल्ली	जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा
2008	26/11 मुंबई हमला	मुंबई	लश्कर-ए-तैयबा (LeT)
2016	उरी सेना अड्डे पर हमला	जम्मू-कश्मीर	पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी
2019	पुलवामा आत्मघाती हमला	जम्मू-कश्मीर	जैश-ए-मोहम्मद (JeM)
2025	पहलगाम हमला	जम्मू-कश्मीर	द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) – जिम्मेदारी ली

आतंकवाद के प्रभाव

- आतंकवाद का प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक सौहार्द, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर व्यापक और दीर्घकालिक होता है। इसके दुष्परिणाम तत्काल और स्थायी दोनों रूपों में प्रकट होते हैं:

1. नागरिकों और सैन्य बलों की जानमाल की हानि

- आतंकवादी हमलों में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की भारी संख्या में मृत्यु होती है। इससे शोक, मानसिक आघात और जनजीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होता है।

2. सुरक्षा और रक्षा व्यय में वृद्धि

- राष्ट्रों को अपने संसाधनों का बड़ा भाग रक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों, और खुफिया सेवाओं में लगाना पड़ता है, जिससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है।

3. पर्यटन और निवेश पर प्रतिकूल असर

- आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्र अस्थिर और असुरक्षित माने जाते हैं, जिससे पर्यटकों और निवेशकों का भरोसा कम होता है। इससे आर्थिक वृद्धि में बाधा आती है।

4. साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण

- धार्मिक या जातीय विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद सामाजिक विभाजन को गहरा करता है, समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ाता है और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देता है।

5. राजनयिक संबंधों पर दबाव

- सीमा पार आतंकवाद के कारण देशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है, विशेषकर जब राज्य या गैर-राजकीय तत्व किसी विदेशी सरकार द्वारा सहारा पाते हैं या संरक्षण में रहते हैं।

6. आंतरिक विस्थापन और मानसिक आघात

- संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे आंतरिक विस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है।
- ऐसे हमलों से बचे व्यक्तियों और समुदायों को लंबे समय तक मानसिक आघात और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ता है।

भारत द्वारा आतंकवाद से निपटने हेतु हालिया प्रयास

- भारत ने आतंकवाद की बदलती प्रकृति और खतरे को देखते हुए इसे रोकने के लिए विधायी, संचालनिक, तकनीकी और कूटनीतिक उपायों पर आधारित बहु-आयामी रणनीति अपनाई है।

1. विधायी उपाय

- UAPA को सशक्त बनाया गया:
- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन कर सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सके, जिससे पूर्व-गिरफ्तारी और संपत्ति ज़ब्ती में सुधार हुआ।
- NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019:
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को अब विदेशों में भी आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार है।
- इसमें मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराध भी जोड़े गए हैं।

2. योजनागत पहल

- **ऑपरेशन ऑल आउट:**
- जम्मू-कश्मीर में सेना, CRPF और स्थानीय पुलिस की समन्वित कार्रवाई द्वारा आतंकियों को निष्क्रिय करने हेतु शुरू किया गया अभियान।
- **ऑपरेशन सिंदूर:**
- अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद TRF से जुड़े आतंकियों को विशेष लक्ष्य बनाकर चलाया गया केंद्रित आतंकवाद-रोधी अभियान।

- ## 3. प्रौद्योगिकी और खुफिया सुधार
- **NATGRID (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड):**
- यह 10 प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझा करने की सुविधा देता है।
- **CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स):**
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपराध और अपराधियों के आंकड़ों तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है।
- **सोशल मीडिया निगरानी:**
- चरमपंथी सामग्री की वास्तविक समय निगरानी और विश्लेषण कर ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और भर्ती को रोकने का प्रयास।

4.कूटनीतिक प्रयास

- **वैश्विक मंचों पर भागीदारी:**
- भारत FATF, UNSC और QUAD जैसे मंचों पर आतंकी वित्तपोषण और खुफिया साझेदारी को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- **संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में दबाव:**
- भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान आधारित आतंकियों को सूचीबद्ध किया जाए, जिससे उनकी वैश्विक फंडिंग और आवाजाही पर रोक लगे।

आतंकवाद अभी भी क्यों बना हुआ है?

- हालाँकि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध कई प्रयास हुए हैं, फिर भी यह खतरा अब भी बना हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कई गहरे भू-राजनीतिक, वित्तीय और वैचारिक कारण हैं।
- इसके अलावा, प्रणालीगत खामियाँ और संचालनिक कमजोरियाँ आतंकवाद को न केवल जीवित रखती हैं, बल्कि समय के साथ इसका स्वरूप भी बदलता जाता है।

आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रमुख वैश्विक कारण

1. राज्य प्रायोजित आतंकवाद

- कुछ राष्ट्र अब भी आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का उपकरण मानते हैं, और गैर-राजकीय तत्वों (non-state actors) को सुरक्षित पनाहगाह, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध कराते हैं।
- उदाहरण: पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), और TRF जैसे संगठनों को लगातार समर्थन देना, दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।

2. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमत की कमी

- आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वीटो नीति प्रभावी और त्वरित कार्रवाई को बाधित करती है।
- भूराजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण कई बार ज्ञात आतंकवादी समूहों या व्यक्तियों के विरुद्ध एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया नहीं बन पाती।

3. जटिल वित्तपोषण नेटवर्क

- आतंकवादी समूह अक्सर गैर-पारदर्शी और अनौपचारिक वित्तीय प्रणालियों का लाभ उठाते हैं जैसे:
- हवाला लेनदेन
- क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से फंड ट्रांसफर
- फ्रंट एनजीओ और नकली धर्मार्थ ट्रस्ट
- ऐसे नेटवर्क को ट्रेस करना और धन के प्रवाह को रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है।

4. छद्म संगठनों की देर से प्रतिबंधित सूची में शामिल करना

- छद्म आतंकवादी संगठन अक्सर नाम बदलकर या नया गठबंधन बनाकर वैश्विक प्रतिबंधों से बच निकलते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति जैसे निकाय जब ऐसे संगठनों को आतंकवादी घोषित करने में देर करते हैं, तो उन्हें खुले तौर पर काम करने की छूट मिलती है।

5. स्थानीय शिकायतों का शोषण

- आतंकवादी नेटवर्क स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असंतोष जैसे —हाशिए पर होना, पहचान का संकट, गरीबी जैसे कारणों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं।
- इससे आतंकवाद केवल सुरक्षा समस्या न रहकर, एक विकास और शासन की चुनौती बन जाता है।

प्रस्तावित रणनीतिक हस्तक्षेप

- आतंकवाद के लगातार बने रहने वाले खतरे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारत और वैश्विक समुदाय को बहुआयामी और सक्रिय रणनीति अपनानी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग (Collaboration)
- प्रौद्योगिकीय नवाचार (Innovation)
- संस्थागत सुधार (Institutional Reform)

आतंकवाद से निपटने हेतु सुझावित रणनीतिक हस्तक्षेप

1. एकीकृत वैश्विक मोर्चे का निर्माण

- अंतरराष्ट्रीय सहमति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) को प्रोत्साहित किया जाए।
- बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से संयुक्त अभियानों, खुफिया साझाकरण, और समन्वित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ किया जाए।

2. वैश्विक निर्णय संरचनाओं में सुधार

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने, आतंकवादियों की शीघ्र सूची बनाने और वीटो-संचालित राजनीति के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समितियों सुधार हेतु प्रयास किए जाएँ
- राज्य प्रायोजकों को जवाबदेह बनाने के लिए सामूहिक राजनयिक दबाव बनाया जाए।

3.प्रारंभिक पहचान के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, और बिग डेटा का उपयोग रीयल टाइम निगरानी और भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग के लिए किया जाए।
- ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और एन्क्रिप्टेड आतंकी संचार का मुकाबला करने हेतु साइबर सुरक्षा ढांचे को मज़बूत किया जाए।

4. समावेशी पुनर्विचार मॉडल को बढ़ावा

- नागरिक समाज, धार्मिक संगठन, और सामुदायिक प्रभावकर्ताओं को पुनर्विचार अभियानों से जोड़ा जाए।
- शिक्षा, रोजगार और जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा को लक्षित किया जाए।

5. बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला

- G20, BRICS, SCO, QUAD जैसे मंचों का उपयोग आतंकी वित्तपोषण, प्रत्यर्पण, और प्रतिबंधों पर सामूहिक कार्यवाही के लिए किया जाए।
- खुफिया सहयोग और सीमा पार कार्यवाही हेतु मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए जाएँ।

6. तेज़-प्रतिक्रिया तंत्र की संस्थागत स्थापना

- नई उभरती आतंकी इकाइयों और व्यक्तियों के लिए त्वरित नामांकन प्रोटोकॉल स्थापित किए जाएँ।
- आतंकी नेटवर्कों के गतिशील डेटाबेस बनाए जाएँ, ताकि फुर्तीली सुरक्षा प्रतिक्रिया संभव हो सके।

निष्कर्ष

- TRF को अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित करना, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है और छद्म आतंक संगठनों के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक सार्थक कदम है।
- लेकिन वास्तविक प्रभाव तभी दिखेगा जब पाकिस्तान जैसे राज्य प्रायोजकों पर लगातार वैश्विक दबाव बनाया जाए।
- भारत को अपने सुरक्षा ढांचे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानूनी कार्रवाई को लगातार मज़बूत करते रहना चाहिए।
- यह कदम आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सामूहिक संघर्ष की शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं।

UPSC Mains के पूर्ववर्ती प्रश्न (PYQs)

- **Q1.** नार्को-आतंकवाद (Narco-terrorism) किस प्रकार देशभर में एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है? इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। (UPSC Mains 2024)
- **Q2.** आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'दिल और दिमाग जीतना' (Winning of Hearts and Minds) जनता का विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है। जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा अपनाए गए ऐसे उपायों की चर्चा कीजिए। (UPSC Mains 2023)
- **Q3.** "भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ अब बाहरी कारकों से भी जुड़ गई हैं।" सीमा-पार आतंकवाद और सीमा प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (UPSC Mains 2021)

Result Mitra Practice Mains Question

- Q. "आतंकवाद केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक चुनौती भी है।"
- छद्म युद्ध और सीमा-पार आतंकवाद के संदर्भ में भारत की रणनीति पर चर्चा कीजिए।